बिरजू

बनाम

स्टेट ऑफ एम.पी.

(आपराधिक अपील कृमांक. 1352-1353 of 2012)

फ़रवरी 14, 2014

[के.एस राधाकृशन और विक्रमाजीत सेन, जेजे.]

दंड संहिता, 1860:

1. हम, इस मामले में, एक वर्ष की आयु के बच्चे की हत्या से चिंतित हैं, जो पीडब्लू 1, दादा की गोद में था, जिसके लिए आरोपी को ट्रायल कोर्ट द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसकी पुष्टि की गई थी उच्च न्यायालय और ये अपीलें अभियुक्त द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302, शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 27 के साथ पठित के तहत अपराध के लिए उसे दी गई सजा और सजा के फैसले के खिलाफ दायर की गई हैं।

2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है:

पीडब्लू1, शिकायतकर्ता 13.12.2009 को लगभग 8.15 बजे कुछ सामान खरीदने के लिए कमल बंसल (पीडब्लू2) की किराने की दुकान पर खड़ा था। उन्होंने अपने एक साल के पोते अरमान को गोद में ले रखा था। पीडब्लू4, जगदीश भी उक्त दुकान के सामने खड़ा था। आरोपी-बिरजू, उसी

इलाके का निवासी, जिसे रुस्तम का बगीचा के नाम से जाना जाता है, मोटरसाइकिल पर वहां से निकला। मोटरसाइकिल खड़ी करने के बाद वह बाबूलाल के पास गया और उससे सवाल किया कि वह वहां क्यों खड़ा है. बाबूलाल ने जवाब दिया कि वह कुछ सामान खरीदने आया है। जबकि, आरोपी-अपीलकर्ता ने शराब पीने के लिए 100/- रुपये की मांग की। बाबूलाल ने पैसे देने में असमर्थता जताई, जिस पर आरोपी ने उसे मां के नाम से गालियां दीं और जेब से देशी पिस्तौल निकालकर गोली मार दी, जो नवजात अरमान के दाहिने कनपटी पर लगी। आवाज सुनकर इलाके के लोग, जिनमें शिकायतकर्ता की बेटी राखी, उसकी चाची शारदा बाई और इलाके के कुछ अन्य निवासी शामिल थे, मौके पर पहुंच गए। शिकायतकर्ता का दामाद जीवन, अरमान को अस्पताल ले गया और पीडब्लू1 तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचा और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई।

3. पीडब्लू 12, थाना प्रभारी, मौके पर पहुंचे और एक स्पॉट मैप (एक्स.पी./2) तैयार किया और शिकायतकर्ता बाबूलाल की खून से सनी शर्ट को जब्ती ज्ञापन (एक्स.पी./3) के जरिए जब्त कर लिया। जब्ती ज्ञापन (एक्सप.पी/6) के माध्यम से मौके से खाली कारतूस, मोटरसाइकिल और प्रयुक्त गोली जब्त की गई। शव पर जांच रिपोर्ट (एक्सटी.पी/8) तैयार की गई, जिसे बाद में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। PW10 डॉ. एके लांगेवार ने पोस्टमार्टम किया।

4. बाद में आरोपी को पकड़ लिया गया और उसके कब्जे से पिस्तौल बरामद कर ली गई और जब्त किए गए सामान को एक्सटी.पी/18-ए के तहत फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, तमिलनाडु में जांच के लिए भेज दिया गया। जांच अधिकारी ने गवाहों के बयान दर्ज किए और जांच पूरी की और आरोपी पर आईपीसी की धारा 302, 327 और 398 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 और 27 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया।

5. अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहों से पूछताछ की और 19 दस्तावेज़ पेश किए और बचाव पक्ष की ओर से किसी से भी पूछताछ नहीं की गई।

6. जैसा कि पहले ही संकेत दिया गया है, मौखिक और दस्तावेजी सबूतों की सराहना करने के बाद, ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया और माना कि आरोपी का मामला "दुर्लभ से दुर्लभतम" श्रेणी में आता है और उसे मृत्युदंड दिया गया, जिसकी उच्च न्यायालय ने पुष्टि की थी। आरोपी को शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत भी दोषी ठहराया गया और तीन साल के कठोर कारावास और 1000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई, जिसकी उच्च न्यायालय ने भी पुष्टि की।

7. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री राणा रणजीत सिंह ने प्रस्तुत किया कि मौजूदा मामला ऐसा नहीं है जो "दुर्लभ से दुर्लभतम" की श्रेणी में आता है, जिसके लिए मृत्युदंड की आवश्यकता है। विद्वान वकील ने बताया कि भले ही पूरे अभियोजन मामले को स्वीकार कर

लिया जाए, फिर भी अपराध आईपीसी की धारा 304 भाग II के तहत कवर किया जाएगा। विद्वान वकील ने यह भी बताया कि आरोपी का PW1 या बच्चे को मारने का कोई इरादा नहीं था। आरोपी, अधिक से अधिक, अत्यधिक मानसिक या भावनात्मक परेशानी में था और भविष्य में उसके लिए इसी तरह के अपराध में शामिल होने का कोई अवसर नहीं होगा, और आरोपी के सुधरने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। विद्वान वकील ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस आधार पर मौत की सजा देने में गलती की है कि आरोपी कई अन्य आपराधिक मामलों में शामिल था, जो वकील के अनुसार, एक गंभीर कारक नहीं हो सकता है। मौत की सज़ा देने के उद्देश्य पर विचार.

8. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री सीडी सिंह ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है। विद्वान वकील ने पीडब्लू4 और पीडब्लू7 के साक्ष्यों का हवाला दिया और कहा कि वे घटना के चश्मदीद गवाह थे और उनके मौखिक साक्ष्य को खारिज करने का कोई कारण नहीं है। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि हत्या निर्मम तरीके से की गई थी और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि आरोपी को दूसरों के जीवन या अंग के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं है। विद्वान वकील ने यह भी कहा कि अभियुक्त के सुधार या पुनर्वास की कोई संभावना नहीं है। विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि, मौजूदा मामले में, अपराध परीक्षण, आपराधिक

परीक्षण और आरआर परीक्षण पूरी तरह से संतुष्ट हैं और ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई मौत की सजा में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।

9. पीडब्लू 1 से 4 और 7 ने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरी तरह से समर्थन किया। पीडब्लू 1, बच्चे के दादा, पीडब्लू 2, 3, 4 और 7 ने उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन जो हुआ उसकी आंखों से देखी तस्वीर पेश की है। उनका संस्करण सुसंगत और अत्यधिक विश्वसनीय है। चश्मदीदों का बयान पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट से पूरी तरह पुष्ट है। बेशक, PW6 को शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया है, लेकिन एक शत्रुतापूर्ण गवाह के साक्ष्य को समग्र रूप से खारिज नहीं किया जा सकता है और उसके प्रासंगिक हिस्से, जो कानून में स्वीकार्य हैं, का उपयोग अभियोजन या बचाव द्वारा किया जा सकता है। सी. मुनियप्पन और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य (2010) 9 एससीसी 567 में इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ लिया जा सकता है। पीडब्लू6 ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपने बयान में कहा है कि, घटना की तारीख पर, उसने PW1 को "गोली मार दी", "गोली मार दी" चिल्लाते हुए सुना, जो इंगित करता है कि, उस हद तक, बयान अभियोजन पक्ष का समर्थन करता है। घटना, जैसा कि पहले ही बताया गया है, 13.12.2009 को लगभग 8.15 बजे एक किराने की दुकान के सामने हुई जब पीडब्लू1 पीडब्लू2 की किराने की दुकान के सामने खड़ा था। उस समय, आरोपी मौके पर पहुंचा और 100/- रुपये की मांग की, जिसे PW1 ने देने

से इनकार कर दिया और, केवल इसी कारण से, उसने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और गोली मार दी, जो एक साल के अरमान के कनपटी क्षेत्र में लगी। वर्ष और वह मर गया.

10. हत्या करने का मकसद जाहिर तौर पर शराब पीने के लिए पैसे जुटाना था, जिसके लिए दुर्भाग्य से एक साल का बच्चा हताहत हो गया। अपराध को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल की गई देशी पिस्तौल बाद में बरामद कर ली गई। PW10, जिसने बच्चे के शव का पोस्टमार्टम किया, ने विभिन्न चोटों को देखा और दोहराया कि गोली मेनिन्जियल झिल्लियों और मस्तिष्क के दोनों हिस्सों को पार कर गई थी। PW10 डॉक्टर की राय थी कि घाव बन्दूक के कारण हुआ था और मृतक की मृत्यु पोस्टमार्टम के 24 घंटे के भीतर हो गई। अभियोजन पक्ष ने मौत के कारण और आरोपी द्वारा आग्नेयास्त्र के उपयोग को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है और हम ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों से पूरी तरह सहमत हैं, जिसकी उच्च न्यायालय ने पुष्टि की है कि आईपीसी की धारा 302 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 27 के तहत अपराध हैं ।, बना दिया गया है।

11. अब हम इस सवाल को लेकर चिंतित हैं कि क्या मामला "दुर्लभतम" की श्रेणी में आता है, जिसमें मौत की सजा दी जानी चाहिए।

12. हमने शंकर किशनराव खाड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य (2013) 5 एससीसी 546 में माना है कि भले ही अपराध परीक्षण और आपराधिक

परीक्षण पूरी तरह से संतुष्ट हो गए हों, मौत की सजा देने के लिए अभियोजन पक्ष को आरआर परीक्षण को संतुष्ट करना होगा। हमने देखा है कि आरोपी को मौत की सजा देने के लिए ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ हाई कोर्ट पर भी जिन कारकों का असर पड़ा, उनमें से एक उसका आपराधिक इतिहास था। उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास से निपटते हुए इस प्रकार कहा:

> "14. अपीलकर्ता का आपराधिक इतिहास है, जो पैराग्राफ 12 में जांच अधिकारी (पीडब्लू-12) मोहन सिंह के बयान से स्पष्ट है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अपीलकर्ता संबंधित पुलिस स्टेशन में एक अधिसूचित बदमाश है और उस पर 24 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसके खिलाफ तीन मामले दर्ज किए थे, जिनमें से तीन मामले हत्या के और दो मामले हत्या के प्रयास के थे। इन सभी मामलों में, जांच के बाद, अपीलकर्ता पर अदालत के समक्ष मुकदमा चलाने के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था। जिरह में बचाव पक्ष की ओर से इस बयान को चुनौती दी गयी. कंडिका 13 में इस गवाह से केवल यह प्रश्न किया गया कि आरोप पत्र के साथ आपराधिक मामलों की सूची दाखिल नहीं की गयी, जिस पर गवाह ने कहा कि यह केस डायरी में उपलब्ध है. इस उत्तर के बाद, अपीलकर्ता के वकील ने अदालत से इस

तथ्य को सत्यापित करने के लिए नहीं कहा और इस गवाह को कोई सुझाव भी नहीं दिया गया कि अपीलकर्ता उपरोक्त सभी आपराधिक मामलों में अभियोजन का सामना नहीं कर रहा था। ये तथ्य यह मानने के लिए पर्याप्त हैं कि अपीलकर्ता को पिस्तौल जैसे घातक हथियार के उपयोग और परिणाम के बारे में पूरी जानकारी थी, और जब उसकी मांग पूरी नहीं हुई; उसने बच्चे अरमान की हत्या करने के लिए जानबूझकर इसका इस्तेमाल किया। चोटों से पता चलता है कि पिस्तौल से बहुत सटीक ढंग से गोली चलाई गई और गोली शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से यानी खोपड़ी को आर-पार कर गई। जब अपीलकर्ता शिशु अरमान को चोट पहुंचाने के लिए आग्नेयास्त्र का उपयोग कर रहा था, तो उसे परिणाम पता होना चाहिए कि ऐसे घातक हथियार के उपयोग के कारण, एक वर्ष की आयु के बच्चे के जीवित रहने की कोई संभावना नहीं होगी।

13. इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने भी, विभिन्न मामलों का उल्लेख करने के बाद, जहां इस न्यायालय ने मौत की सजा सुनाई थी, वर्तमान मामले को दुर्लभ से दुर्लभतम माना और इस प्रकार कहा:

"26. उपरोक्त कानूनी स्थिति के आलोक में इस बात पर विचार करने के लिए कि क्या तत्काल मामला दुर्लभ से दुर्लभतम की श्रेणी में आता है, हम निम्नलिखित परिस्थितियों की कल्पना करते हैं:-

i) अपराध अत्यधिक मानसिक या भावनात्मक अशांति के प्रभाव में नहीं किया गया था।

ii) अपीलकर्ता लगभग 45 वर्ष का काफी परिपक्व व्यक्ति है। वह न तो जवान है और न ही बूढा।

iii) उसके आपराधिक इतिहास को देखते हुए यानी उस पर 24 आपराधिक मामलों के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था, जिनमें से 3 " आईपीसी " की धारा 302 के तहत थे और 2 " आईपीसी " की धारा 307 के तहत थे, इसलिए, कोई संभावना नहीं है कि आरोपी भविष्य में हिंसा का कार्य नहीं करेगा और समाज में उसकी उपस्थिति समाज के लिए निरंतर खतरा बनी रहेगी।

iv) अपीलकर्ता के सुधार या पुनर्वास की कोई संभावना या संभावना नहीं है।

v) वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, आरोपी/अपीलकर्ता अपने द्वारा एक वर्ष की आयु के बच्चे की हत्या को नैतिक रूप से उचित नहीं ठहरा सकता।

vi) यह कहने के लिए कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सबूत उपलब्ध नहीं है कि आरोपी ने किसी अन्य व्यक्ति के दबाव या प्रभुत्व के तहत काम किया।

vii) अपीलकर्ता/अभियुक्त की स्थिति ऐसी नहीं थी, जिससे यह पता चले कि वह मानसिक रूप से दोषपूर्ण था और उक्त दोष ने उसके आचरण की आपराधिकता को समझने की उसकी क्षमता को कमजोर कर दिया।

viii) यह पूरी तरह से निर्मम हत्या है और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य इस तथ्य को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि अपीलकर्ता को दूसरों के जीवन और अंगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है।"

14. मौत की सज़ा की पुष्टि करने के लिए उच्च न्यायालय के पास जो कारक थे, उनमें से एक यह था कि आरोपी पर 24 आपराधिक मामलों को अंजाम देने के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था, जिनमें से तीन आईपीसी की धारा 302 के तहत थे और दो आईपीसी की धारा 307 के तहत थे, परिणामस्वरूप न्यायालय ने माना कि इस बात की कोई संभावना

नहीं है कि आरोपी भविष्य में हिंसा का कार्य नहीं करेगा और उसकी उपस्थिति समाज के लिए लगातार खतरा बनी रहेगी। न्यायालय ने यह भी विचार किया कि अभियुक्त के सुधार या पुनर्वास की कोई संभावना या सम्भावना नहीं है।

15. हमने शंकर किसनराव खाड़े के मामले (सुप्रा) में इस सवाल पर विचार किया है कि क्या अभियुक्त के पिछले आपराधिक रिकॉर्ड को मौत की सजा देते समय ध्यान में रखा जाना एक गंभीर परिस्थिति होगी और माना गया कि केवल कुछ आपराधिक मामलों का लंबित होना इस प्रकार, मृत्युदंड देते समय इस पर ध्यान देने की कोई गंभीर परिस्थिति नहीं है, क्योंकि उन मामलों में अभियुक्त को दोषी नहीं पाया जाता है और दोषी नहीं ठहराया जाता है। वर्तमान मामले में, यह कहा गया था, कि आरोपी 24 आपराधिक मामलों में शामिल था, जिनमें से आरोपी के खिलाफ तीन हत्या के मामले और दो मामले हत्या के प्रयास के दर्ज थे और, उन सभी मामलों में, आरोपी पर आरोप था- कानून की अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए दाखिल किया गया। यह दिखाने के लिए हमारे सामने कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है कि आरोपी को इनमें से किसी भी मामले में दोषी ठहराया गया था। अभियुक्त पर केवल आरोप-पत्र दायर किया गया है और उसे दोषी नहीं ठहराया गया है, इसलिए, आरआर परीक्षण लागू करते समय उस कारक पर ध्यान दिया जाना प्रासंगिक कारक नहीं है ताकि मृत्युदंड दिया जा सके। हो सकता है, किसी दिए गए मामले में, आरोपी व्यक्ति के

खिलाफ बड़ी संख्या में आपराधिक मामलों का लंबित होना एक ऐसा कारक हो सकता है जिसे सजा देने में ध्यान दिया जा सकता है, लेकिन किसी भी मामले में, मृत्युदंड देने के लिए यह एक प्रासंगिक कारक नहीं है। सच है, जब दो दर्जन से अधिक मामले होते हैं, जिनमें से तीन हत्या के अपराध से संबंधित होते हैं, तो बचाव पक्ष द्वारा झूठे आरोप की सामान्य दलील को पीछे की सीट पर रखा जाना चाहिए, और सजा नीति पर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि अभियुक्त की उपस्थिति समाज के लिए एक सतत ख़तरा हो सकती है और इसलिए लंबी अवधि की कारावास की आवश्यकता है।

16. हम गंभीर परिस्थितियों के निर्धारण में विभिन्न मानदंड निर्धारित करते समय, दो पहलुओं पर भी ध्यान देते हैं, जिनका उल्लेख अक्सर बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) 2 एससीसी 684, मच्छी सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य (1983) में देखा जाता है।) 3 एससीसी 470 और राजेंद्र प्रल्हादराव वासनिक बनाम महाराष्ट्र राज्य (2012) 4 एससीसी 37, (1) आरोपी द्वारा पूर्व में हत्या, बलात्कार, सशस्त्र डकैती, अपहरण आदि जैसे जघन्य अपराध करने से संबंधित अपराध हैं। गंभीर हमलों और आपराधिक सजा का पर्याप्त इतिहास रखने वाले व्यक्ति द्वारा किए गए गंभीर घोर अपराध या अपराधों के लिए सजा का रिकॉर्ड; और (2) अपराध तब किया गया जब अपराधी किसी अन्य गंभीर अपराध को अंजाम देने में लगा हुआ था। आरआर परीक्षण लागू करते समय पहला

मानदंड एक प्रासंगिक कारक हो सकता है, बशर्ते हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे जघन्य अपराधों से संबंधित अपराध सजा में समाप्त हो गए हों।

17. हम पहले जांच कर सकते हैं कि क्या "गंभीर हमलों और आपराधिक सजा का पर्याप्त इतिहास" एक गंभीर परिस्थिति है जब अदालत हत्या, बलात्कार, सशस्त्र डकैती आदि जैसे जघन्य अपराधों से संबंधित अपराधों से निपट रही है। दोषसिद्धि का पूर्व रिकॉर्ड, में हमारा विचार, एक प्रासंगिक कारक होगा, लेकिन उस दोषसिद्धि को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए ताकि इसे मौत की सजा देने के लिए गंभीर परिस्थिति के रूप में माना जा सके। दूसरा पहलू उस स्थिति से संबंधित है जहां एक अपराध किया गया था, जबकि अपराधी किसी अन्य गंभीर अपराध को अंजाम देने में लगा हुआ था। यह एक ऐसी स्थिति है जहां अभियुक्त एक और गंभीर अपराध करने में लगा हुआ है जो दोषसिद्धि में समाप्त नहीं हुआ है और अंतिम परिणाम तक पहुंच गया है।

18. वर्तमान मामले में, न्यायालय ने यह विचार किया कि इस बात की कोई संभावना नहीं है कि आरोपी हिंसा के आपराधिक कृत्य नहीं करेगा और समाज के लिए निरंतर खतरा बनेगा और ऐसी कोई संभावना नहीं होगी कि आरोपी को सुधारा जा सके या उसका पुनर्वास किया जा सके। . शंकर किसनराव खाड़े के मामले (सुप्रा) में, आपराधिक परीक्षण (परिस्थितियों को कम करने) से निपटने के दौरान, इस न्यायालय ने देखा

कि परीक्षण लागू करते समय ट्रायल कोर्ट द्वारा विचार की जाने वाली परिस्थितियों में से एक, अभियुक्त की संभावना के संबंध में है। दोबारा अपराध में लिप्त होना और आरोपी के सुधार और पुनर्वास की संभावना। हमने पाया है कि, कई मामलों में, ट्रायल कोर्ट आपराधिक परीक्षण लागू करते समय, बिना किसी सामग्री के, या तो यह मान लेगा कि अभियुक्त के अपराध में शामिल होने की कोई संभावना नहीं होगी या वह भविष्य में ऐसे अपराधों में शामिल होगा और इसलिए, उसे सुधारना या पुनर्वास करना संभव नहीं होगा। अदालतें कुछ छोटे अपराधों में सुधारात्मक सिद्धांत लागू करती थीं और व्यक्तियों को दोषी ठहराते समय, अदालतें कभी-कभी सीआरपीसी की धारा 360 और अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 3 और 4 के संदर्भ में आरोपियों को परिवीक्षा पर रिहा कर देती थीं । अधिनियम परिवीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति और निष्पादित किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति का प्रावधान करता है। धारा 4 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए अदालतें भी परिवीक्षा अधिकारी से रिपोर्ट मांगती हैं। हमारे विचार में, उचित मामलों में सजा सुनाते समय, सीआरपीसी की धारा 235(2) के तहत आरोपी की सुनवाई करते समय , अदालतें अपराध परीक्षण दिशानिर्देश संख्या 3 को लागू करते हुए प्रोबेशन अधिकारी से रिपोर्ट भी मांग सकती हैं, जैसा कि निर्धारित है शंकर किसनराव खाड़े के मामले में नीचे (सुप्रा)। अदालत तब जांच कर सकती है कि क्या आरोपी

के किसी अपराध में शामिल होने की संभावना है या आरोपी के सुधार और पुनर्वास की कोई संभावना है।

19. हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि आरोपी को पूरी जानकारी थी, अगर वह कनपटी पर यानी माथे और कान के बीच में गोली चलाता, तो एक साल के बच्चे की मौत हो जाती। PW1 की भुजाएँ। बेशक, अपीलकर्ता ने पीडब्ल्यू 1 से 100/- रुपये की मांग की, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया और फिर उसने अपनी मांग पूरी न करने के प्रतिशोध के रूप में पिस्तौल निकाली और बच्चे के दाहिने कनपटी क्षेत्र पर गोली चला दी और ऐसा दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। घटना के समय वह शराब के नशे में था। नतीजतन, दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए, हम यह कहने के लिए तैयार नहीं हैं कि यह दुर्लभतम मामला है, जिसमें मृत्युदंड की आवश्यकता है। इसलिए, हम ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई मौत की सजा को रद्द कर देते हैं और उसे आजीवन कारावास में बदल देते हैं।

20. हालाँकि, हमारा विचार है कि यह एक उपयुक्त मामला है जहाँ हम स्वामी श्रद्धानंद (2) उर्फ मुरली मनोहर शर्मा बनाम कर्नाटक राज्य (2008) 13 एससीसी 767 में निर्धारित सिद्धांत को लागू कर सकते हैं। उस मामले में, इस न्यायालय ने विचार किया कि मामलों की एक तीसरी श्रेणी है जिसमें न्यायालय, आजीवन कारावास की सजा सुनाते समय,

मृत्युदंड के बजाय 14 या 20 साल के कारावास की अवधि (छूट के साथ या बिना) तय कर सकता है और कर सकता है। उचित मामलों में, आदेश दें कि सज़ाएँ लगातार चलेंगी, साथ-साथ नहीं। इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त सजा नीति को कई मामलों में अपनाया गया है, तब से, नवीनतम गुरवेल सिंह बनाम पंजाब राज्य (2013) 10 एससीसी 631 है। हमने संकेत दिया है कि यह एक ऐसा मामला है जहां आरोपी चौबीस आपराधिक मामलों में शामिल है। जिनमें से तीन हत्या के अपराध के लिए हैं और दो हत्या के प्रयास के लिए हैं। ऐसी परिस्थितियों में, यदि अपीलकर्ता को कम सजा दी जाती है और रिहा कर दिया जाता है, तो वह समाज के लिए खतरा होगा।

21. हमारा विचार है कि यह एक उपयुक्त मामला है जहां अपीलकर्ता को बिना किसी छूट के 20 साल का कठोर कारावास, उस अवधि के दौरान जो वह पहले ही भुगत चुका है, पर्याप्त सजा होगी और पर्याप्त न्याय प्रदान करेगी। तदनुसार आदेश दिया गया।

22. उपरोक्तानुसार अपीलों का निपटारा किया जाता है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी नीतू आर्य (आर.जे.एस) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझााने की सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।